भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

24.07.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 344 का उत्तर

महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में परियोजनाएँ

344. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री प्रवीण पटेल:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चल रही रेलवे परियोजनाओं की संख्या, उनकी लंबाई, लागत, तथा ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त परियोजनाओं की सूची, परियोजना की प्रकृति, मार्ग, पूरा होने की संभावित तिथि, प्रत्येक परियोजना में देरी के कारण क्या हैं;

(ग) पिछले 10 वर्षों में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में रेलवे के लिए औसत वार्षिक बजट कितना है;

(घ) महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लिए 2023-24 का बजट और प्रमुख शीर्षों के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अमृत भारत योजना के लिए चयनित स्टेशनों की सूची और सुधार के लिए प्रस्तावित उपाय क्या हैं;

(च) महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में पुनर्विकास के लिए चयनित स्टेशन कौन से हैं; और

(छ) वे स्टेशन कौन-कौन से हैं जहां ठाणे, कल्याण और डोंबिवली स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन चल रहे हैं और उनकी प्रगति क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 24.07.2024 को लोक सभा में डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री प्रवीण पटेल और श्री नरेश गणपत म्हस्के के अतारांकित प्रश्न सं. 344 के भाग (क) से (छ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ) : रेल परियोजनाएं क्षेत्रीय रेल-वार स्वीकृत की जाती हैं न कि राज्य-वार या क्षेत्र-वार क्योंकि भारतीय रेल परियोजनाएं विभिन्न राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हुई हैं।

<u>महाराष्ट्र</u>

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, पिछले महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली 81,580 करोड़ रु लागत की 5,877 कि.मी. की कुल लंबाई की 41 रेल अवसंरचना परियोजनाएं (16 नई लाइनें, 02 आमान परिवर्तन और 23 दोहरीकरण) योजना/कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 1,926 कि.मी. लंबाई कार्य का कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक 31,236 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है। इसमें शामिल हैं:-

(i) 38,423 करोड़ रु. की लागत वाली 2,017 कि.मी. कुल लंबाई की 16 नई लाइन परियोजनाएं हैं, जिनमें से 166 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 8,529 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है।

(ii) 7,339 करोड़ रु. की लागत वाली 609 कि.मी. कुल लंबाई की 2 आमान परिवर्तन परियोजनाएं हैं, जिनमें से 312 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 3,332 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है।

(iii) 35,818 करोड़ रुपये की लागत वाली 3,251 कि.मी. कुल लंबाई की 23 दोहरीकरण परियोजनाएं हैं, जिनमें से 1,448 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 19,376 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।

वर्ष 2014 से, भारतीय रेल के निधि आबंटन में पर्याप्त वृद्धि हुई है और परियोजनाओं के अनुरूप कमीशनिंग की जा रही है। महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतया/आंशिक रूप से होने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाएं एवं संरक्षा कार्यों के लिए बजट आवंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	औसत परिव्यय	2009-14 के दौरान औसत आवंटन के संबंध में वृद्धि
2009-14	1,171 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष	-
2014-24	7,197 करोड़ रुपये/वर्ष	6.1 गुना
2023-24	13,539 करोड़ रुपये	11.56 गुना

महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतया/आंशिक रूप से आने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की कमीशनिंग निम्नानुसार है:

अवधि	कमीशन की गई कुल रेलपथ	कमीशन की गई औसतन रेलपथ	2009-14 के दौरान औसत कमीशनिंग के संबंध में वृद्धि
2009-14	292 कि.मी.	58.4 कि.मी. प्रति वर्ष	-
2014-24	1830 कि.मी.	183 कि.मी. प्रति वर्ष	3.13 गुना

2023-24 में, कुल 358 किलोमीटर रेलपथ की कमीशनिंग की गई है, जो 2009-14 के दौरान की गई औसत कमीशनिंग की तुलना में 6 गुना अधिक है।

इसके अलावा, उपनगरीय गलियारों पर भीड़भाड़ से बचने और भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए 10,947 करोड़ रुपये की लागत पर एमयूटीपी-III और 33,690 करोड़ रुपये की लागत पर एमयूटीपी-IIIए को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं में निम्नलिखित अतिरिक्त 10 रेल

संपर्क शामिल हैं:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लागत (₹ करोड़ में)
1	पांचवीं और छठी लाइन सीएसटीएम-कुर्ला (17.5 किमी)	891
2	छठी लाइन मुंबई सेंट्रल-बोरीवली (30 किमी)	919
3	पनवेल-करजत उपनगरीय गलियारा (29.6 किमी)	2782
4	ऐरोली-कलवा (एलिवेटेड) उपनगरीय कॉरिडोर लिंक (3.3 किमी)	476
5	विरार-दहानु रोड की तीसरी और चौथी लाइन (64 किमी) का चौहरीकरण	3587
6	हार्बर लाइन गोरेगांव-बोरीवली का विस्तार (7 किमी)	826
7	पांचवीं और छठी लाइन बोरीवली-विरार (26 किमी)	2184
8	कल्याण-आसनगांव के बीच चौथी लाइन (32 किमी)	1759
9	कल्याण-बदलापुर के बीच तीसरी और चौथी लाइन (14.05 किमी)	1510
10	कल्याण यार्ड-मेन लाइन और उपनगरीय लाइन का पृथक्करण	866

इन सभी एमयूटीपी परियोजनाओं को रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच लागत भागीदारी के आधार पर 50:50 के आधार पर स्वीकृत किया गया है। बहरहाल, महाराष्ट्र सरकार मार्च 2022-23 तक प्रतिबद्धता के अनुसार समय पर अपेक्षित धनराशि प्रदान नहीं कर रही थी, जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं के पूरा होने में देरी हुई। महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल 2023 से एमयूटीपी-IIIए परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण शुरू कर दिया है।

<u>उत्तर प्रदेश</u>

01.04.2024 तक, उत्तर प्रदेश में 68 रेल परियोजनाएं (16 नई लाइन, 03 आमान परिवर्तन और 49 दोहरीकरण), 92,001 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 5,874 कि.मी. लंबाई

वाली, जो पूरी तरह/आंशिक रूप से राज्य में आती हैं, जिनमें से 1,313 कि.मी. लंबाई को कमीशन किया गया है और मार्च 2024 तक 28,366 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। इसमें शामिल हैं-

(i) 29,156 करोड़ रु. की लागत वाली 1,740 कि.मी. कुल लंबाई की 16 नई लाइन परियोजनाएं हैं, जिनमें से 297 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 8,672 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है।

(ii) 2453 करोड़ रु. की लागत वाली 261 कि.मी. कुल लंबाई की 3 आमान परिवर्तन परियोजनाएं हैं, और मार्च 2024, तक 26 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है।

(iii) 60,392 करोड़ रुपये की लागत वाली 3,873 कि.मी. कुल लंबाई की 49 दोहरीकरण परियोजनाएं हैं, जिनमें से 1,016 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 19,668 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।

वर्ष 2014 से, भारतीय रेल के बजट आबंटन में पर्याप्त वृद्धि की गई है और परियोजनाओं के अनुरूप कमीशनिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतया/आंशिक रूप से आने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाएं एवं संरक्षा कार्यों के लिए बजट आवंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	औसत परिव्यय	2009-14 के दौरान औसत आवंटन के संबंध में वृद्धि
2009-14	1,109 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष	-
2023-24	8833 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष	7.96 गुना

उत्तर प्रदेश में पूर्णतया/आंशिक रूप से आने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की कमीशनिंग निम्नानुसार है:

अवधि	कमीशन किया गया कुल रेलपथ	औसत परिव्यय	2009-14 के दौरान औसत कमीशनिंग के संबंध में वृद्धि
2009-14	996 कि.मी.	199.2 कि.मी/प्रति वर्ष	-
2014-24	4902 कि.मी.	490.2 कि.मी/प्रति वर्ष	2.46 गुना

रेल परियोजनाओं का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृति, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृति, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना/परियोजनाओं स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण विशेष परियोजना स्थल के लिए एक वर्ष में कार्य महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजनाओं के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं।

रेल परियोजनाओं के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं (i) निधियों के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि, (ii) क्षेत्र स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन, (iii) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी (iv) त्वरित भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव स्वीकृति और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों के समाधान हेतु राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों सहित नियमित अनुवर्ती कार्रवाई।

(ङ) से (छ): भारतीय रेल पर रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए 'अमृत भारत स्टेशन योजना' शुरू की गई है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है।

इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर आवश्यकता को देखते हुए मास्टर प्लान तैयार करना और रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं जैसे रेलवे स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालयों, शौचालयों में यथा आवश्यक सुधार, आवश्यकता के अनसुार लिफ्ट/एस्केलेटर, स्वच्छता, मुफ्त वाई-फाई, 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए

कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामोदिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि में सुधार लाने के लिए उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल है।

इस योजना में लंबी अवधि के दौरान आवश्यकता, चरणबद्धता एवं व्यवहार्यता के अनुसार रेलवे स्टेशन भवन में सुधार, रेलवे स्टेशन का शहर की दोनों तरफ के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था और रेलवे स्टेशन पर सिटी सेन्टर्स के निर्माण की संकल्पना भी की गई है।

इस योजना के अंतर्गत अब तक 1324 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है जिनमें से 128 स्टेशन महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं और 157 स्टेशन उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। ठाणे और कल्याण रेलवे स्टेशनों पर मास्टर प्लानिंग शुरू की गई है जो एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया है जिसमें इष्टतम और विवरण की आवश्यकता होती है। इसलिए, इस चरण में कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

महाराष्ट्र राज्य में 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के अंतर्गत विकास के लिए चिह्नित किए गए स्टेशनों के नाम इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	राज्य	संख्या	स्टेशनों के नाम
1	महाराष्ट्र	128	अहमदनगर, अजनी (नागपुर), अक्कलकोट रोड़, अकोला, अकुर्डी, अमलनेर, आमगाँव, अमरावती, अंधेरी, औरंगाबाद, बडनेरा, बल्हारशाह, बांद्रा टर्मिनस, बारामती, बेलापुर, भंडारा रोड, भोकर, भुसावल, बोरीवली, भायकुला, चालीसगाँव, चंदा फोर्ट, चंद्रपुर, चर्नी रोड, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, चिंचपोकली, चिंचवाड, दादर, दौंड, देहुरोड, देवलाली, धामनगांव, धरनगांव, धर्माबाद, धुले, दिवा, दूधानी, गंगाखेर, गोधानी, गोंदिया, ग्रांट रोड, हडपसर, हथकनांगले, हज़ूर साहिब नांदेड़, हिमायत नगर, हिंगनघाट, हिंगोली, दक्कन इगतपुरी, इतवारी, जलगाँव, जालना, जेरूर, जोगेश्वरी, कल्याण, कैम्पटी, कंजुरमार्ग रोड, कराड,

क्र.सं.	राज्य	संख्या	स्टेशनों के नाम
			काटोल, केडगाँव, किनवट, कोल्हापुर, कोपरगाँव, कुर्डुवाड़ी, कुर्ला, लासलगाँव, लातूर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, लोनंद, लोनावाला, लोअर परेल, मलाड, मलकापुर, मनमाड, मनवट रोड, मरीन लाइन्स, माटुंगा, मिराज, मुदखेड़, मुंबई सेंट्रल, मुंब्रा, मुर्तिजापुर, नागरसोल, नागपुर, नंदगाँव, नांदुरा, नरखेड़, नासिक रोड, उस्मानाबाद, पचोरा, पालघर, पंढरपुर, परभनी, परेल, परली वैजनाथ, परतुर, प्रभादेवी, पुलगाँव, पुणे जं., पूर्णा, रावेर, रोटेगांव, साईंनगर शिर्डी, सैंड्रस्ट रोड, सांगली, सतारा, सावदा, सेलू, सेवाग्राम, शहाद, शेगांव, शिवाजी नगर पुणे, सोलापुर, तालेगांव, ठाकुरली, ठाणे, टिटवाला, तुमसर रोड, उमरी, उरुली, वडाला रोड, विद्याविहार, विक्रोली, वडसा, वर्धा, वाशिम, वाथर, नंदूरबार, फलटण

****